माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार व जसवंत सिंह के समक्ष

हकीम किशोरी लाल शिक्षा महाविद्यालय, — याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य — उत्तरदाता गण

2008 की **C.W.P.** संख्या **7974**

13 अगस्त, 2009

भारत का संविधान, ***1950*** — अनुच्छेद ***226*** — राष्ट्रीय परिषद शिक्षक शिक्षा अधिनियम, ***1993*** — धारा ***3*** और ***12***-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, ***2007***- विनियम.***8(3)*** और ***(4)***-शिक्षक प्रवेश की सीटों में वृद्धि शिक्षा पाठ्यक्रम-बी.एड सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन करने वाले याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता ***2007*** के विनियमों के प्रावधानों को पूरा नहीं कर रहे हैं-दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान रूप से स्थित संस्थानों के पक्ष में आदेश पारित किया-याचिकाएं स्वीकार की गईं, प्रतिवादियों को एक प्रवेश की मंजूरी के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया बी.एड पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त इकाई।

अभिनिर्धारित किया गया, विनियम *8(3)* और *8(4)* जो *2005* के विनियमों में शामिल किए गए थे, *2006* के विनियमों द्वारा वापस ले लिए गए और *2007* के विनियमों में फिर से शामिल किए गए। याचिकाकर्ता सोसायटी को एनसीटीई की उत्तरी क्षेत्रीय समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र *2006-2007* के लिए *10* अगस्त, *2006* को *100* (एक यूनिट) के वार्षिक प्रवेश के साथ एक वर्ष के बी.एड पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की गई थी। प्रासंगिक समय पर जब याचिकाकर्ता सोसायटी को प्रारंभिक मंजूरी दी गई थी, *2006* के विनियम *(20* जुलाई, *2006* की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित) लागू थे और *2005* विनियम के नियम*8(3)* और *8(4)* में निर्धारित शर्तें लागू नहीं थे।

(पैरा 24)

आगे अभिनिर्धारित किया गया, प्रत्येक याचिका में विवादित संचार को रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या *2* और *3* तीन शैक्षणिक सत्र आयोजित करने की पात्रता मानदंड और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के साथ मान्यता की आवश्यकता पर जोर नहीं देंगे। NAAC ने 2007 के विनियमों के विनियम 8(3) और 8(4) में विचार किया गया है। वे शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 के लिए दायर बी.एड पाठ्यक्रम के लिए एक अतिरिक्त इकाई के प्रवेश के अनुमोदन के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को अन्य विनियमों के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से संसाधित करेंगे।

(पैरा 35)

संजय मजीठिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ

जशनप्रीत सिंह गिल, एडवोकेट, याचिकाकर्ता के लिए।.

प्रतिवादी सं. *1* के लिए कोई नहीं

विनोद एस. भारद्वाज एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या *2* और *3* के लिए

पीयूष कांत जैन, अतिरिक्त एजी, पंजाब, प्रतिवादी सं. *4* के लिए

प्रतिवादी *5* के लिए नहीं

एम.एम. कुमार, न्यायाधीश :

(1) यह आदेश 2008 के सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 728 और 7974 का निपटान करेगा जिनमे कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं। हालाँकि, तथ्यों को C.W.P 2008 की संख्या 7974 से संदर्भित किया जा रहा है। .

(2) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर यह याचिका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2007 (संक्षिप्तता के लिए, '2007 विनियम') की शक्तियों को चुनौती देती है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद द्वारा अधिसूचित किया गया है। शिक्षा [संक्षिप्तता के लिए, 'एनसीटीई' संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है (पी-11)]। 'एनसीटीई' के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पारित 18 फरवरी, 2008 के आदेश को रद्द करने के लिए। एक और प्रार्थना की गई है, जिसके तहत 'एनसीटीई' द्वारा पहले से ही मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में अतिरिक्त प्रवेश के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। फिर भी 27 नवंबर, 2007 (पी-13) के 'एनसीटीई' के विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से आवेदन करने की सलाह के साथ लौटा दिया गया है। फिर भी यह प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को 100 सीटें (एक इकाई) आवंटित करके शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में अतिरिक्त प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए।

(3) मामले के तथ्यों पर पहले गौर किया जा सकता है। पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के योजनाबद्ध और समन्वित विकास को प्राप्त करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') अधिनियमित किया गया था जो 1 जुलाई, 1995 यानी इसी तारीख को लागू हुआ जबसे। सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना अधिसूचित हुई थी।

(4) अधिनियम का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण मौजूदा विवाद की पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए उपयोगी होगा। अधिनियम की धारा 3 में एक परिषद की स्थापना पर विचार किया गया है

जिसे 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद' ('एनसीटीई') कहा जाएगा। अधिनियम की धारा 12 'एनसीटीई' के कार्यों से संबंधित है और उप-खंड (एफ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने और भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएं, स्टाफिंग पैटर्न और स्टाफ योग्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित करता है। . अधिनियम की धारा 13 यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'एनसीटीई' द्वारा निरीक्षण का प्रावधान करती है कि क्या मान्यता प्राप्त संस्थान उक्त अधिनियम के प्रावधानों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

(5) अधिनियम की धारा 14 शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता से संबंधित है। धारा 14 की उप-धारा (1) के अनुसार, प्रत्येक संस्थान जो नियत दिन पर या उसके बाद शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की पेशकश करता है या देने का इरादा रखता है, उसे अनुदान के लिए 'एनसीटीई' की संबंधित क्षेत्रीय समिति को आवेदन करना आवश्यक है। अधिनियम के तहत मान्यता. यहां यह जानना प्रासंगिक है कि 17 अगस्त, 1995 को 'नियत दिन' के रूप में तय किया गया है।

(6) अधिनियम 'एनसीटीई' के कामकाज में पारदर्शिता भी लाता है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, एक मान्यता प्राप्त संस्थान, जो शिक्षक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने का इरादा रखता है, को भी अनुमति लेने के लिए एक आवेदन करना आवश्यक है। 'एनसीटीई' की संबंधित क्षेत्रीय समिति। अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) में आगे विचार किया गया है कि शिक्षक शिक्षा में एक नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान को अनुमति देने या अस्वीकार करने वाले प्रत्येक आदेश को अनिवार्य रूप से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और उचित के लिए लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था और संबंधित जांच निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कार्रवाई।

(7) अधिनियम की धारा 16 संबद्ध निकाय के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान को संबद्धता प्रदान करने या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाती है, जब तक कि ऐसे संस्थान ने संबंधित क्षेत्रीय समिति से ऐसा पाठ्यक्रम अधिनियम की धारा 14 के तहत एनसीटीई संचालित करने की अनुमति प्राप्त नहीं की हो।

<u>विनियम 8(3) और(4) और सेवन में वृद्धि के लिए दो शर्तें</u>

(8) 27 दिसंबर, 2005 को एनसीटीई ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, '2005 विनियम') को अधिसूचित किया, जिसमें पात्रता, आवेदन करने का तरीका और समय सीमा, प्रसंस्करण सहित विभिन्न प्रावधान निर्धारित किए गए। आवेदनों की संख्या, मान्यता प्रदान करने की शर्तें आदि आदि (पी-4 ए)। 2005 के विनियम 8 में मान्यता प्रदान करने के लिए विस्तृत शर्तें निर्धारित की गई हैं। 2005 विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (3) के अनुसार, एक संस्थान संबंधित पाठ्यक्रमों को चलाने के तीन शैक्षणिक सत्रों के पूरा होने के बाद पहले से

अनुमोदित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि के लिए आवेदन करने का हकदार था। 2005 विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियमन (4) में आगे कहा गया है कि एक संस्थान को माध्यमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम-बी.एड. में प्रवेश बढ़ाने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। एवं बी.पी. एड., यदि इसने खुद को एनएएसी द्वारा विकसित ग्रेड बी अक्षर के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (संक्षिप्तता के लिए, 'एनएएसी') से मान्यता प्राप्त कर ली है।

विनियमन 8 (3) और (4) का विलोपन

(9) 20 जुलाई, 2006 (पी-5) को, एनटीसीई ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006 (संक्षिप्तता के लिए, '2006 विनियम') को अधिसूचित करते हुए एक और अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उपर्युक्त 2005 के विनियम 8 के उप-विनियम (3) और (4) को हटा दिया गया। हालाँकि, 2007 विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियमों (3) और (4) द्वारा समान शर्तोंको फिर से पेश किया गया था।

(10) याचिकाकर्ता सोसायटी ने पात्र होने के नाते अधिनियम की धारा 14(1) के तहत बी.एड पाठ्यक्रम की अनुदान मान्यता के लिए आवेदन किया। 10 अगस्त, 2006 को 'एनसीटीई की उत्तरी क्षेत्रीय समिति के क्षेत्रीय निदेशक ने याचिकाकर्ता सोसायटी को बी.एड. संचालित करने के लिए अधिनियम की धारा 14(3)(ए) के तहत मान्यता प्रदान की। शैक्षणिक सत्र 2006-2007 के लिए 100 (एक इकाई) के वार्षिक प्रवेश के साथ एक वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम, कुछ शर्तों (पी-2) की पूर्ति के अधीन था।

(11) 11 अगस्त, 2006 को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की एक समिति द्वारा निरीक्षण करने के बाद अनंतिम संबद्धता भी प्रदान की गई थी। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा याचिकाकर्ता सोसायटी को बी.एड. संचालित करने की अनुमति दी गई। सत्र 2006-07 के लिए 100 सीटों की क्षमता वाला पाठ्यक्रम (पी-3)। 19 जुलाई, 2007 को, पंजाब विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2007-08 (पी-4) के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी और अन्य कॉलेजों को संबद्धता का अनंतिम विस्तार दिया।

(12) याचिकाकर्ता मंडी गुरु हर सहाय, जिला फिरोजपुर की एक चैरिटेबल सोसायटी है और 9 जनवरी, 1996 से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज, पंजाब, चंडीगढ़ के साथ विधिवत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता सोसायटी एक नर्सिंग कॉलेज और एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन चला रही है। , अर्थात्, एच.के.एल. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुरु हरसहाय।

(13) याचिकाकर्ता सोसायटी ने बी.एड. का प्रवेश बढ़ाने का निर्णय लिया। शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए सीटें 100 से 200 तक। 27 अक्टूबर, 2007 को, याचिकाकर्ता सोसायटी ने रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपना आवेदन पंजाब विश्वविद्यालय, प्रतिवादी संख्या 5 को प्रस्तुत

किया। 50,000 (पी-6 और पी-7)। 6 नवंबर, 2007 को याचिकाकर्ता सोसाइटी ने रुपये का एक और डिमांड ड्राफ्ट भेजा। सेवन में वृद्धि के शुल्क के लिए 2,000 (पी-8 और पी-9)। दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता सोसायटी ने रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार कराए। 40,000 प्रत्येक, दिनांक 26 दिसंबर, 2007, सदस्य सचिव, एनसीटीई के पक्ष में और रुपये की एफडीआर। 50,000, दिनांक 27 दिसंबर, 2007, और उसे 27 दिसंबर, 2007 को क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई-प्रतिवादी नंबर 3 को भेजकर बी.एड में 100 प्रवेश सीटें बढ़ाने का अनुरोध किया गया। (प-10)

(14) इस बीच, 'एनसीटीई' ने 27 नवंबर, 2007 को एक अधिसूचना जारी की, जो 10 दिसंबर, 2007 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई। उक्त अधिसूचना के माध्यम से, एनसीटीई ने 2007 के विनियमों को अधिसूचित किया है। 2007 विनियम के विनियम 5 के उप-विनियम (4) के अनुसार, 'एनसीटीई' की संबंधित क्षेत्रीय समिति को आवेदन जमा करने की कट-ऑफ तिथि शैक्षणिक सत्र से पिछले वर्ष की 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिसके लिए मान्यता मांगी जानी है। 2007 विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (5) में आगे यह निर्धारित किया गया है कि वर्ष के 31 अक्टूबर को या उससे पहले प्राप्त सभी पूर्ण आवेदनों को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए संसाधित किया जाएगा और अंतिम निर्णय अगले वर्ष के 15 मई तक सूचित किया जाएगा। . 2007 विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय के लिए आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कमी को इंगित करना अनिवार्य है, जिसे आवेदक 90 दिनों के अंदर हटा सकते हैं । मान्यता प्रदान करने की शर्तें जो दिनांक 20 जुलाई, 2006 (पी-5) की अधिसूचना द्वारा वापस ले ली गई थीं, उन्हें फिर से लागू किया गया (पी-11)। 2007 के विनियमों का विनियम 11 असाधारण मामलों में एनसीटीई के अध्यक्ष को विनियमों के प्रावधानों में ढील देने की शक्ति देता है। हालाँकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है।

(15) 18 फरवरी, 2008 को, क्षेत्रीय निदेशक एनसीटीई- प्रतिवादी संख्या 3 ने 2007 के विनियम 8 के उप-विनियम (3) और (4) का उल्लेख करने के बाद याचिकाकर्ता सोसायटी के आवेदन को अतिरिक्त प्रवेश के लिए वापस कर दिया। आधार यह है कि याचिकाकर्ता सोसायटी उक्त प्रावधानों को पूरा नहीं करती है। 2007 विनियम (पी-13) के प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से आवेदन करने की सलाह दी गई है।

(16) यह दावा किया गया है कि 23 फरवरी, 2008 को, याचिकाकर्ता ने पंजाब सरकार के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग-प्रतिवादी संख्या 4 को अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली को नियम 5(4) में ढील देने की सिफारिश करने के लिए प्रस्तुत किया था।) और 2007 विनियमों के 8(4) और बी.एड. के छात्रों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी के मामले पर विचार करें। शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए पाठ्यक्रम। उक्त अभ्यावेदन को अध्यक्ष एनसीटीई (पी-14) को भी समर्थन दिया गया था।

(17) पंजाब विश्वविद्यालय-प्रतिवादी संख्या 5 के सिंडिकेट ने 23 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में याचिकाकर्ता सोसायटी को बी.एड. के संबंध में संबद्धता का अनंतिम विस्तार देने का निर्णय लिया। (1 इकाई) सत्र 2008-09 के लिए संबद्धता जारी रखने का मामला है। हालाँकि, बी.एड के संबंध में। (2 इकाई) इसका निर्णय 'एनसीटीई' द्वारा अनुमोदन के बाद किया जाना था (पी-15)।

(18) 15 अप्रैल, 2008 को, उप निदेशक (कॉलेज), पंजाब ने भी पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को याचिकाकर्ता सोसायटी के पक्ष में अतिरिक्त प्रवेश देने के लिए मामले को एनसीटीई के साथ उठाने की सिफारिश की। (पी-16).

(19) यह आरोप लगाया गया है कि सीटों की मान्यता/अतिरिक्त प्रवेश के लिए आवेदनों पर विचार करते समय 'एनसीटीई' द्वारा चयन और चयन की नीति अपनाई गई है। क्षेत्रीय निदेशक एनसीटीई-प्रतिवादी नंबर 3 के पास मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। विभिन्न नए पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटें देने के लिए भी अधिकृत है। यह दावा किया गया है कि कुल मिलाकर 50 आवेदन वापस कर दिए गए, - आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2008 (पी-13) के अनुसार। हालाँकि, उनमें से कोई भी राजस्थान राज्य का नहीं था। याचिकाकर्ता सोसायटी ने राजस्थान राज्य (पी-17) से संबंधित 15 आवेदकों की सूची भी रिकॉर्ड में रखी है, जिन्होंने बी.एड./बी.पी.एड के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए आवेदन किया है। 11 नवंबर, 2007 को या उसके बाद, लेकिन 18 फरवरी, 2008 के आदेश में ऐसे आवेदकों का कोई उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता सोसायटी ने उत्तरदाताओं को 11 अप्रैल, 2008 को एक कानूनी नोटिस भी भेजा। (पी-18)

(20) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 जिन्होंने प्रतिवाद करने वाले उत्तरदाताओं ने लिखित बयान दाखिल किया है, जबकि अन्य उत्तरदाताओं की ओर से कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अधिनियम, 2005, 2006 और 2007 विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के पुनरुत्पादन के बाद, यह प्रस्तुत किया गया है कि 'एनसीटीई' ने एक सचेत नीतिगत निर्णय लिया है कि प्रारंभिक चरण में या बाद में बी.एड में अतिरिक्त प्रवेश के लिए। पाठ्यक्रम में 100 छात्रों वाली केवल एक इकाई को संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमति दी जाएगी, जिसे अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। 'एनसीटीई' ने अधिनियम की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर विनियम तैयार किए हैं, जो बाध्यकारी बल के साथ वैधानिक प्रकृति के हैं। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता सोसायटी को एनआरसी, जयपुर द्वारा 8 अगस्त, 2007 के आदेश के तहत अतिरिक्त प्रवेश की अनुमति दी गई है, और इस प्रकार, उसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। 1 अप्रैल, 2010 से पहले एनएएसी द्वारा विकसित व्यू ग्रेडिंग सिस्टम के तहत एक पत्र ग्रेड बी, ऐसा न करने पर दी गई अतिरिक्त प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से वापस ले ली जाएगी।

(21) 17 अप्रैल 2009 को याचिकाकर्ता सोसायटी ने सिविल विविध दायर किया। इसी तरह के विवाद से जुड़े मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों और आदेशों के संदर्भ में तत्काल याचिका के निपटान के लिए 2009 का आवेदन संख्या 6976। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की प्रतियां भी रिकॉर्ड पर रखी गई हैं (पी-19 से पी-24 और पी-26)। यह निहित है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों को लागू कर दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की गई है।

(22) 20 जुलाई, 2009 को, जब मामला हमारे सामने सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ता सोसायटी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का संदर्भ दिया और तर्क दिया कि विनियमन 8(3) और 8 के प्रावधान (4) 2007 के विनियम प्रतिवादी एनसीटीई पर लागू नहीं हुए हैं क्योंकि एनसीटीई ने कुछ मामलों में रियायत दी है और बाद के मामलों में प्रतिस्पर्धा के बावजूद, आवेदक के पक्ष में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा आदेश पारित किया गया है- संस्थान, जो वर्तमान याचिकाकर्ताओं के समान स्थित हैं। उस संबंध में डब्ल्यू.पी. में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों पर भरोसा किया गया है। (सी) 2000 की संख्या 1119 (शिक्षा परिषद कणय गुरुकुल जुलालना बनाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) [अनुलग्नक पी-19 से पी-23] और बुद्ध के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1 अगस्त, 2008 कॉलेज ऑफ एजुकेशन और अन्य बनाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद [2008 का डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5131] और अन्य संबंधित याचिका (पी-26)।

(23) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा किए गए उपरोक्त विशिष्ट दावों के मद्देनजर, उन संस्थानों की सटीक संख्या जानना आवश्यक था जिनके मामलों में 2007 के विनियम 8(3) और 8(4) की आवश्यकता है आराम दिया गया. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, 22 जुलाई, 2009 और 28 जुलाई, 2009 को विद्वान वकील से समय मांगने और देने के बावजूद आज तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है। तदनुसार, हमने मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया।

(24) हमने पार्टियों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया है। यह स्वीकार किया गया है कि विनियम 8(3) और 8(4), जिन्हें 2005 के विनियमों में शामिल किया गया था, 2006 के विनियमों द्वारा वापस ले लिए गए और 2007 के विनियमों में फिर से शामिल कर दिए गए। बी.एड. की मान्यता प्रदान करना। एनसीटीई की उत्तरी क्षेत्रीय समिति (पी-2) द्वारा याचिकाकर्ता सोसायटी को शैक्षणिक सत्र 2006-2007 के लिए 10 अगस्त, 2006 को 100 (एक यूनिट) के वार्षिक प्रवेश के साथ एक वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम प्रदान किया गया था। प्रासंगिक समय पर जब याचिकाकर्ता सोसायटी को प्रारंभिक मंजूरी दी गई थी, 2006 के विनियम (20 जुलाई, 2006 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित) लागू थे और विनियम 8(3) और 8(4) में निर्धारित शर्तें लागू

थीं और 2005 के नियम लागू नहीं थे। उचित समझ के लिए 2005 के विनियम 8(3) और 8(4) को पढ़ना उचित होगा:-

"8. मान्यता प्रदान करने की शर्तें

(1)

(2)

(3) किसी संस्थान को संबंधित पाठ्यक्रम चलाने के तीन शैक्षणिक सत्रों के पूरा होने के बाद पहले से अनुमोदित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रवेश बढ़ाने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) किसी संस्थान को माध्यमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम-बी.एड. में प्रवेश बढ़ाने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। और बी.पी.एड. कार्यक्रम, यदि इसने खुद को एनएएसी द्वारा विकसित लेटर ग्रेड बी के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त कर लिया है।"

(26) 2007 के विनियम 5(4) में पहली बार एक कट-ऑफ तारीख पेश की गई जिसके द्वारा एक आवेदन जमा करना आवश्यक था, और वह तारीख भी निर्धारित की गई जिसके द्वारा उत्तरदाता अनुदान देने या इनकार करने के लिए अंतिम संचार भेजेंगे। मान्यता प्रदान करें. जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी जा रही थी, उससे पहले वर्ष के 31 अक्टूबर तक आवेदन जमा करना आवश्यक था। इसलिए, शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 के लिए, आवेदन 31 अक्टूबर, 2007 तक जमा किया जाना चाहिए था। चूंकि 2007 के विनियम 10 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किए गए थे, यानी 31 अक्टूबर, 2007 की अंतिम तिथि के बाद, 'एनसीटीई 'ने निम्नलिखित आशय की एक सार्वजनिक सूचना जारी की:-

> *"*यह स्पष्ट किया जाता है कि *31* अक्टूबर*, 2007* के बाद भी प्राप्त आवेदनों को अगले शैक्षणिक सत्र*, 2008-09* के लिए संसाधित किया जा सकता है*,* बशर्ते कि किसी विशेष शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए संस्थान को मान्यता प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें पूरी की जाएं। हालांकि*,* कोई मान्यता नहीं*/* शैक्षणिक सत्र *2008-09* के लिए किसी संस्थान को अनुमति *15* मई *2008* के बाद दी जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह छूट केवल चालू वर्ष के लिए है और *31* अक्टूबर की कट ऑफ तारीख *31* अक्टूबर से सख्ती से प्रभावी होगी। *2008* यानी शैक्षणिक सत्र *2009-2010* से पहले।*"*

(27) यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि समान आदेशों द्वारा, जैसा कि तत्काल याचिकाओं में लगाया गया है, एनसीटीई ने भी बड़ी संख्या में संस्थानों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। उनमें से कुछ संस्थानों ने 2007 के विनियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने वाले मामले द्वारा निपटाया गया। 21 मई, 2008 को, जब शिक्षा परिषद कन्या गुरुकुल जुलाना (सुप्रा) का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो प्रतिवादी एनसीटीई की ओर से उपस्थित वकील श्री वी.के. राव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्पष्ट बयान दिया कि "इस आवेदन के प्रसंस्करण और अनुमोदन के उद्देश्य से प्रतिवादी इन दो मानदंडों पर जोर नहीं देगा"। उल्लिखित मानदंड 2007 के विनियम 8(3) और 8(4) में निहित थे

जैसा कि पिछले पैरा में पुन: प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिट याचिका का निपटारा 29 मई, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर दिया गया क्योंकि इस बीच, उस संस्थान का निरीक्षण 'एनसीटीई' की क्षेत्रीय समिति द्वारा किया गया था, जिसमें पाया गया कि अनुमोदन के लिए शर्तें पूरी की गई थीं। इसलिए, डब्ल्यू.पी में याचिकाकर्ता (सी) 2008 की संख्या 1119 (सुप्रा), 'एनसीटीई' ने मंजूरी दे दी 2007 के विनियम 8(3) और 8(4) के अनुपालन पर जोर दिए बिना विनियम। विनियम 8(3) और 8(4) को चुनौती देने के संबंध में प्रश्न 2007 के विनियमों को खुला छोड़ दिया गया था। इसके बाद, 21 मई को आदेश दिया गया, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2008 के डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1119 में पारित किया गया (सुप्रा) और इस प्रकार जो व्यवस्था बनी, उसका तीन अन्य रिटों में पालन किया गया जिन याचिकाओं का इसी तरह 11 जून 2008 को निपटारा किया गया श्री वी.के. द्वारा पहले दी गई रियायत का नोट राव, वकील 2008 के डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1119 (सुप्रा) में प्रतिवादी। अत: यह स्पष्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त रियायत सीमित थी न केवल एक याचिकाकर्ता यानी 2008 के WP(C) नंबर 1119 (सुप्रा) में बल्कि था तीन अन्य याचिकाकर्ताओं तक विस्तारित, अर्थात्, WP(C) संख्या 4507, 450 और 2008 का 4512. 2008 की WP(C) संख्या 4582 नामक एक अन्य रिट याचिका थी। इसी तरह 26 जुलाई, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया गया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर 'एनसीटीई' द्वारा दी गई रियायत पर गौर किया। 2008 के WP(C) नंबर 1119 (सुप्रा) में और एक निर्देश दिया कि प्रतिवादी 'एनसीटीई' तीन अकादमिक होने की पात्रता मानदंड पर जोर नहीं और साथ ही विनियम 8 में दिए गए एनएएसी के साथ मान्यता की आवश्यकता पर भी जोर नहीं देगा। एक इकाई द्वारा सेवन क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से 2007 विनियमों के 3) और 8(4)। दो अन्य रिट याचिकाएँ, WP(C) संख्या 4625 और 4674, 2008 का दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 1 जुलाई, 2008 और 10 जुलाई, 2008 को इसी तरह निपटारा किया गया था।

(28) जब 2008 की डब्ल्यूपी(सी) संख्या 4674 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए लिया गया था, तो 'एनसीटीई' के विद्वान वकील ने आग्रह किया था कि उपरोक्त मामलों में और विशेष रूप से डब्ल्यूपी(सी) में रियायत दी गई थी।) 2008 की संख्या 1119, लेकिन 'एनसीटीई' उस प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए 2008 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4674 में समान रियायत देने को तैयार नहीं थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल यह तथ्य कि 'एनसीटीई' उस विशेष मामले में समान रियायत देने को तैयार नहीं था, याचिकाकर्ता को उसी राहत से वंचित करने का कारण नहीं हो सकता है जो अन्य समान रूप से स्थित संस्थानों को दी गई थी, क्योंकि ' एनसीटीई' अपनी कार्रवाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए बाध्य है और बिना किसी औचित्य के समान स्तर पर स्थित संगठनों के साथ अलग-अलग स्तर पर व्यवहार नहीं कर सकता है।

(29) इसके बाद, जब बुद्ध कॉलेज ऑफ एजुकेशन (सुप्रा) और अन्य संबंधित मामले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आए, तो 'एनसीटीई' के वकील श्री अमितेश कुमार ने अदालत को अवगत कराया कि एनसीटीई' ने 2008 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1119 (सुप्रा) में आदेश की समीक्षा की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया है जिसमें श्री वी.के. द्वारा दी गई रियायत राव, अधिवक्ता दर्ज किया गया था। तब यह आग्रह किया गया था कि 2007 के

विनियम 8(3) और 8(4) के संबंध में उक्त रियायत पर जोर नहीं दिया गया था, जो निर्देशों के बिना दी गई थी।

(30) 'एनसीटीई' द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 25 जुलाई, 2008 को निपटा दिया, अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए कि 21 मई, 2008 का आदेश स्वयं व्याख्यात्मक था और इसमें विस्तार या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। . इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 'एनसीटीई' की इस दलील को स्वीकार नहीं किया है कि उक्त रियायत बिना निर्देशों के दी गई थी और उसने 'एनसीटीई' को उस विशेष मामले यानी 2008 के डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1119 (सुप्रा) में राहत नहीं दी है।), अपने वकील के माध्यम से दी गई रियायत के बारे में।

(31) बुद्ध कॉलेज ऑफ एजुकेशन (सुप्रा) और अन्य संबंधित याचिकाओं के मामले का विरोध करने के लिए, 'एनसीटीई' के वकील ने 28 जुलाई, 2008 के एक आदेश पर भी भरोसा किया, जो इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया था। ब्रहस्पति महिला महाविद्यालय बनाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (सीएम संख्या 7998/2008 और सीएम संख्या 9289/2008 डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4108 ऑफ 2008 में)। उस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा समान दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए उपरोक्त आवेदन दायर किए गए थे और उस उद्देश्य के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों पर भी भरोसा किया गया था जैसा कि ऊपर देखा गया है। इसके बावजूद, डिवीजन बेंच ने उक्त मामले में याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए अंतरिम अनिवार्य निर्देश देने से इनकार कर दिया।

(32) दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष बुद्ध कॉलेज ऑफ एजुकेशन (सुप्रा) और संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान, 'एनसीटीई' के विद्वान वकील ने भी माननीय के निर्णयों पर भरोसा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनाम कर आयुक्त, बी.एस.[1] के मामले में प्रतिपादित किया। बाजवा बनाम पंजाब राज्य[2], अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड बनाम शम्मी भान[3] और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध बनाम डॉ. के. संतकुमारी[4] और तर्क दिया कि एक वकील द्वारा दी गई कानून में रियायत किसी पार्टी की ओर से, उस पार्टी को बाध्य नहीं किया जा सकता।

(33) उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति पर विचार करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि 'एनसीटीई' को उन शैक्षणिक संस्थानों से अलग व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिनकी याचिकाएँ पहले ही दी गई रियायतों के आधार पर अनुमति दे चुकी हैं। 'एनसीटीई' ने बार-बार अपने अधिकृत परामर्श के माध्यम से। बुद्ध कॉलेज ऑफ एजुकेशन (सुप्रा) और संबंधित याचिकाओं के मामले में

1 (1998) 2 एस.सी.सी. 264
2 (1998) 2 एस.सी.सी. 523
3 (1998) 6 एस.सी.सी. 538
4 (2001) 5 एस.सी.सी. 60

दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 1 अगस्त, 2008 का ऑपरेटिव भाग निम्नानुसार निकाला गया है: -

...प्रासंगिक रूप से, रियायत सबसे पहले श्री वी.के. द्वारा दी गई थी। राव, अधिवक्ता. ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद न तो श्री रवि सीकरी और न ही श्री अमितेश कुमार उससे विचलित हुए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित 11 जून, 2008 और 1 जुलाई, 2008 के आदेशों से स्पष्ट होगा। मेरे विचार में, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों का इन मामलों के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन विनियमों के तहत प्रतिवादी संस्थानों को मान्यता देने के लिए मानदंडों और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, वे एनसीटीई द्वारा ही बनाए जाते हैं और समय-समय पर एनसीटीई द्वारा संशोधित किए जाते हैं। यह एनसीटीई ही है जो इन याचिकाओं में प्रतिवादी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एनसीटीई की ओर से रेगुलेशन 5(4) को लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी की जा चुकी है. इसलिए, एनसीटीई ने समय-समय पर अपने मानदंडों और विनियमों में ढील देने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। हालाँकि, छूट देते समय यह समान रूप से स्थित संस्थानों के बीच भेदभावपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि विनियमन 8(3) और 8(4) की छूट अवैध है, एनसीटीई की क्षमता से परे है या नियमों के विपरीत है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विनियम 8(3) और 8(4) में छूट के संबंध में प्रतिवादी के वकील द्वारा दी गई रियायत, जैसा कि शुरुआत में WP(C) संख्या 1119/2008 में दर्ज किया गया था, नहीं दी जा सकती थी। , कि उक्त छूट प्रतिवादी को बाध्य नहीं कर सकती; और यह कि उक्त रियायत विनियमों के विपरीत थी। जहां तक 20 जुलाई, 2008 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का संबंध है, उक्त आदेश से ऐसा नहीं लगता है कि माननीय डिवीजन बेंच श्री वी.के. द्वारा दी गई रियायत के प्रभाव में आ गई है। राव द्वारा शुरू में, और जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसका प्रभाव इस न्यायालय की डिवीजन बेंच और एकल बेंचों द्वारा बार-बार किया जा रहा है। इसलिए, मेरे विचार में, उक्त आदेश को इस न्यायालय के दृष्टिकोण के उलट नहीं माना जा सकता है, जो कि उपरोक्त सभी आदेशों में अभिव्यक्ति पाता है।

11 तदनुसार, WP(C) संख्या 1119/2008 और उपरोक्त पैराग्राफ 5 में वर्णित विभिन्न अन्य रिट याचिकाओं में इस न्यायालय के निर्णयों का पालन करते हुए। मैं निर्देश देता हूं कि बी.एड./डी.एड./एसटीसी पाठ्यक्रम के लिए एक अतिरिक्त इकाई के प्रवेश के अनुमोदन के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदाताओं को तीन शैक्षणिक सत्र रखने की पात्रता मानदंड और आवश्यकता पर जोर नहीं देना चाहिए। जैसा कि 10 दिसंबर, 2007 के विनियमों के विनियम 8(3) और 8(4) में विचार किया गया है, एनएएसी से मान्यता प्राप्त है। इनमें से प्रत्येक याचिका में विवादित संचार को रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी को शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 के लिए एक यूनिट के अतिरिक्त सेवन के लिए इन याचिकाकर्ताओं के मामले को अन्य नियमों के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से संसाधित करने का निर्देश दिया जाता है।

12. याचिकाकर्ताओं के वकील बताते हैं कि यदि 16 सितंबर, 2008 तक मान्यता नहीं दी गई, तो याचिकाकर्ता वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2008-2009 में छात्रों को प्रवेश देने की स्थिति में नहीं होगा। याचिकाकर्ता वचन देते हैं कि वे अपनी ओर से प्रतिवादी के साथ सहयोग करेंगे और याचिकाकर्ताओं को जो भी आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी, उन्हें पूरा करने में कोई देरी नहीं

होगी। यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से कोई देरी नहीं होती है, तो उत्तरदाता 7 सितंबर, 2008 तक आवेदनों का निपटान करने का प्रयास करेंगे ताकि वे शैक्षणिक सत्र 2008-09 से बढ़े हुए प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम शुरू करने में सक्षम हो सकेंअगर मंजूरी दी जा रही है तो।

(34) प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 के विद्वान वकील श्री विनोद एस. भारद्वाज उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को सफलतापूर्वक खारिज करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने केवल इतना कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जो निर्णय के लिए लंबित है। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभी भी प्रासंगिक है।

(35) हमें उसी दृष्टिकोण को अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई समान मामलों में लगातार अपनाया है। तदनुसार, हम इन याचिकाओं को अनुमति देते हैं। इनमें से प्रत्येक याचिका में विवादित संचार को रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 तीन होने की पात्रता मानदंड पर जोर नहीं देंगे शैक्षणिक सत्र के साथ-साथ मान्यता की भी आवश्यकता है एनएएसी जैसा कि 2007 के विनियम 8(3) और 8(4) में विचार किया गया है विनियम. वे याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे बी.एड. हेतु एक अतिरिक्त यूनिट के प्रवेश हेतु अनुमोदन। पाठ्यक्रम के लिए दायर किया गया शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 सख्ती से दूसरे के अनुसार यथाशीघ्र विनियम करें। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील वचन देता है कि वे उत्तरदाताओं के साथ सहयोग करेंगे याचिकाकर्ताओं की अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई देरी नहीं होगी मिलने की उम्मीद है. यदि की ओर से कोई देरी नहीं होती है याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी निपटाने का प्रयास करेंगे ।15 सितंबर 2009 तक आवेदन करें ताकि वे शुरू हो सकें शैक्षणिक सत्र 2009-10 से बढ़े हुए प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्थिति मे।

(36) रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा